

शैक्षणिक उत्थान की चुनौतियाँ “मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा के संदर्भ में”

Dr. Arjun Singh Bhaghel*

Assistant Principal (Commerce) Rani Durgawati Govt. PG College, Mandla (MP)

सारांश :- देश के विकास में उच्च शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के माध्यम से सामाजिक राजनैतिक, एवं आर्थिक परिवर्तन सम्भव है। आज के बदलते परिवेश में वैश्विक अर्थव्यवस्था ज्ञान प्रदान करने वाली ईकाई के रूप में शिक्षा किसी देश के विकास की मुख्य धारा से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण कड़ी है। सही शिक्षा जीवन के प्रत्येक पहलू पर पहुँच रखती है। अच्छी शिक्षा वह होगी, जो हमारे भूतकाल से उत्तम बातों को ग्रहण कर सकें, वर्तमान का श्रेष्ठ उपयोग कर सकें, साथ ही भविष्य की दिशा भी निर्धारित कर सकें। प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक अरस्तु के अनुसार – “शिक्षा का लक्ष्य व्यक्ति की आत्मा की निश्चित तथा आंतरिक दशाओं को अभिव्यक्त करना है।”

व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है अतः उसके लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह समाज में रहते हुए स्वयं को सामाजिक संहिता से समायोजित करने का प्रयास करें। ऐसे व्यक्ति जो स्वयं को समायोजित नहीं कर पाते हैं वे समाज तथा समाज के सदस्यों के लिए समस्या पैदा करते हैं।

आज देश के ज्यादातर शैक्षणिक संस्थाओं में शैक्षणिक वातावरण दूषित होता चला जा रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो शिक्षण संस्थाओं में छात्रों और शिक्षकों के निजी जीवन में उदत्त नैतिक आदर्शों का घोर अभाव है। शिक्षा का उद्देश्य मूल रूप से चरित्र का निर्माण करना है। शिक्षा मनुष्य को संस्कारवान और मानवीय चरित्र को उदात्तीकृत करने का सबसे कारगर हथियार है। डॉ. जे. बी. विलनिलम का मानना है कि—“शिक्षा को मानव संसाधन विकास में राष्ट्रीय निवेश के रूप में लिया जाना चाहिए। जवाबदेही के प्रश्न पर नीति निर्धारण एवं वित्तीय संस्थाओं को गहन विचार करना होगा क्योंकि इस क्षेत्र में लागत अधिक और वसूली निम्न है।”

शब्दकुंजी :- शून्यकक्षा, प्रतिभाबैंक, फीडबैक, एम्बेडेड प्राध्यापक, गुरुकुल शिक्षा पद्धति, पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली।

-----X-----

परिचय:-

शिक्षा किसी भी राष्ट्र और समाज की दशा और दिशा को निर्धारित करती है। शिक्षा एक सतत प्रवाहमान प्रक्रिया है। हमारे जीवन को गतिशील बनाने में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्राचीन काल में गुरुकुल प्रणालियों में विद्यार्थी हर प्रकार की शिक्षा ग्रहण करते थे। प्राथमिक रूप से उन्हें समुची विधाओं और विद्याओं की मूलभूत जानकारी दी जाती थी। भारत में ब्रिटिश शासन काल की प्रतिष्ठा के साथ ही वर्तमान शिक्षा नीति का प्रचलन हुआ। विचित्र बात यह है कि स्थापना के साथ ही उसका विरोध भी शुरू हो गया और वह आजकल जारी है। विडम्बना यह है कि हम पाश्चात्य शिक्षा पद्धति का विरोध लगभग 100 वर्षों से कर रहे हैं और आज तक उसको पूरी तरह से बदल नहीं पाए हैं। जबकि यह आरोप लगता रहा है कि समस्त चिंतन यूरोपीय शिक्षा पद्धति के अधीन है। फलतः इस दुविधापूर्ण शिक्षा के संदर्भ में भारतीय व्यक्ति पनप नहीं पा रहा है। शिक्षित हाने के उपरांत भी हमारे अधिकांश विद्यार्थियों को बेकार रहना पड़ता है। यह दुविधापूर्ण स्थिति है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार “शिक्षा वह दीपक है जो व्यक्ति के अंदर के तम को समाप्त कर उसे संसार में प्रदीप्तमान करती है।” यदि हमें समाज के विकास

को सही दिशा प्रदान कर अपनी दशा में परिवर्तन लाना है तो हमें अपनी उच्च शिक्षा के बुनियादी ढाँचे में परिवर्तन करने होंगे।

विश्लेषण :-

सरकार उच्च शिक्षा के विकास हेतु सतत रूप से प्रयासरत् है। इस सिलसिले में सरकार द्वारा लागू की गई पंचवर्षीय योजनाओं में शिक्षा को प्रोत्साहन देने एवं उपयोगी बनाने हेतु किए जाने वाले व्ययों में निरन्तर वृद्धि की गई है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में 153 करोड़ रुपये, आठवीं पंचवर्षीय योजना में 21217 करोड़ रुपये नवीं पंचवर्षीय योजना में 22096 करोड़ रुपये, दसवीं पंचवर्षीय योजना में 43825 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पहले उच्च शिक्षा गरीब व्यक्ति की पहुँच से बाहर थी, परन्तु आज प्रवेश हेतु प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से सभी लोगों को समानता का अवसर प्रदान कर शिक्षा प्राप्ति को आसान बना दिया जा रहा है। प्रतिभाशाली एवं गरीब छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्तियाँ प्रदान की

जा रही है। नाम मात्र का शिक्षण शुल्क लेकर छात्रों को शिक्षण हेतु निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध कराई जा रही है।

मध्यप्रदेश में उच्च शिक्षा के शैक्षणिक उत्थान हेतु प्रदेश के समस्त महाविद्यालयों में उच्च शिक्षा के गुणवत्तापूर्ण विकास हेतु सतत रूप से कार्य किया जा रहा है। उनमें मुख्य रूप से भाषा सुधार अभियान, खाली एवं शून्य कक्षाओं को उत्पादक कक्षाओं में बदलना, प्रतिभा बैंक का गठन करना एवं फीडबैक व्यवस्था का विकास, एम्बेसेडर प्राध्यापक योजना का संचालन, ऑनलाइन एडमिशन का क्रियान्वयन किया जा रहा है। शैक्षणिक उत्थान के यह प्रयास सराहनीय हैं। कई नई योजनाएँ विद्यार्थियों के लिए शुरू की गईं। जिसके तहत छात्राओं के लिए गाँव की बेंटी योजना, प्रतिभा किरण योजना, यातायात भत्ता ये योजनाएँ सम्पूर्ण देश भर में एक उदाहरण के रूप में पेश की गई हैं। शैक्षणिक उत्थान में यह एक सकारात्मक कदम है।

हमारी शिक्षा प्रणाली की कुछ बहुत अच्छी विशेषताएँ हैं और कहीं ये दोषपूर्ण भी हैं। इसलिए शैक्षणिक उत्थान की अनेकों चुनौतियाँ हमारे सामने हैं। अधिकांश महाविद्यालयों में आवश्यक आधारभूत शोध सम्बंधी सुविधाओं, लेबोरेटरी, मानक के अनुसार भवन, खेल सुविधाओं एवं पुस्तकालयों में पुस्तकों का अभाव है। निजी व सरकारी महाविद्यालयों में कार्यालयीन स्टाफ के अभाव में कार्यालय सम्बंधी कार्य भी प्राध्यापकों द्वारा ही किये जाते हैं, जिससे भी शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होती है। परीक्षाओं का दौर महीनों चलतना रहता है। ऊपर से थोपी गई ढेरों प्रादेशिक एवं राष्ट्रीय कार्य योजनाओं का संचालन करने में शैक्षणिक गतिविधियों की समयावधि का ह्रास होता है।

मध्यप्रदेश में उच्च शिक्षा में वर्षों से कई पद खाली पड़े हैं। नई नियुक्तियाँ नहीं हो रही हैं। तदर्थ नियुक्तियों से काम चल रहा है। तदर्थवाद आज की शिक्षा का यथार्थवाद बन गया है। देश के 300 विश्वविद्यालयों और 16000 कॉलेजों में से हर साल 25,00,000 विद्यार्थी पढ़ कर निकलते हैं। दुनिया की शीर्ष 300 विश्वविद्यालयों में एक भी भारतीय विश्वविद्यालय नहीं है, जबकि चीन के 6 विश्वविद्यालय इस सूची में शामिल हैं 17 से 24 साल के करीब 7.2 फीसदी युवाओं को ही उच्च शिक्षा हासिल हो पाती है, जबकि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में यह दर 88 फीसदी और ब्रिटेन में 22 फीसदी है। उक्त कमियों के पीछे संसाधनों की कमियों को भले ही जिम्मेदार पहलू माना जाए परन्तु यदि शिक्षा के स्तर को प्रभावशाली बनाने हेतु अनिवार्य कदम उठाये जाए तो संसाधनों के अभाव के बावजूद भी शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है।

महाविद्यालय एवं उच्च शिक्षा के अन्य संस्थानों में नियुक्तियों में भाई-भतीजावाद तथा घटिया राजनैतिक प्रभाव ने उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में ह्रास पैदा किया है। पी.एच.डी. जैसी डिग्री भी केवल नौकरी प्राप्त करने या वरिष्ठ वेतनमान प्राप्त करने का साधन मात्र बनकर रह गई है। ऐसी स्थिति में शैक्षणिक उत्थान अपेक्षा अनुरूप नहीं हो पा रहा है। हमें इस बात को भी गम्भीरता से समझना होगा। आज शिक्षा का परिदृश्य काफी बदल गया है। हमें नवाचारों को प्रोत्साहित करना होगा।

शैक्षणिक उत्थान के संदर्भ में सुधार की चुनौतियाँ अपार हैं। विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के शिक्षकों के लिए प्रतिवर्ष शिक्षण व प्रशिक्षण के कार्यक्रम आयोजित किये जाएँ। शिक्षण कार्य को अधिक प्रभावी बनाने की तकनीकों पर भी विचार विमर्श किया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम संख्या में महाविद्यालय

स्थापित किए जाँ। ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की विशेषकर कुअभ्र एवं लघु उद्योगों की स्थापना की जाए। इससे गाँवों को विकास भी होगा तथा नगरीय क्षेत्र में आबादी का दबाव भी कम होगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि पाठ्यक्रम में ग्रामीण जीवन से सम्बंधित प्रसंगों का समावेश किया जाए। परम्परागत पाठ्यक्रमों को रोजगार आधारित (जॉब ओरिएंटेड) बनाया जाए। कुशल प्रशिक्षित एवं प्रबंध के ज्ञान में परिपूर्ण कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि के लिए उच्च शिक्षा में रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रमों में प्रवेश को बढ़ावा दिया जाए। फेकल्टी पर शिक्षण का भार कम किया जाए, तथा शोध पर ज्यादा ध्यान केन्द्रित किया जाए। उद्यमिता पर आधारित प्रशिक्षण पर जोर दिया जाए। फायनेंस, मार्केटिंग, एच.आर, हेल्थ केयर आदि क्षेत्रों में स्पेशलाइजेशन दिया जाना चाहिए। शिक्षक, छात्र अनुपात में सुधार किया जाए। विषय विशेषज्ञों की बेहतर विशेषज्ञता हासिल की जाए। उपरोक्त कमियों को दूर करने हेतु उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उपर्युक्त सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इन सभी में सुधार की आवश्यकता है। इस हेतु संयुक्त प्रयास एवं विचार करने होंगे।

निष्कर्ष :-

उच्च शिक्षा की वर्तमान चुनौतियों में शिक्षक, शिक्षार्थी, शैक्षणिक संरचना और शैक्षणिक वातावरण, ये चार प्रमुख घटक हैं। वर्तमान दशा और दिशा सुधारने के लिए इन घटकों में सकारात्मक प्रयास करने की आवश्यकता है। उच्च शिक्षा जगत के समक्ष अनेक चुनौतियाँ मुँह बाएँ खड़ी हैं। वर्तमान में शिक्षा के क्षेत्र में भी समरसता का अभाव होता जा रहा है। पूर्व में शैक्षणिक संस्थानों में प्राचार्य-प्राध्यापक के सम्बंध मधुर थे। आज इस सम्बंध में प्रतिस्पर्धा आ गई है। प्राध्यापक-छात्र सम्बंध भी व्यावसायिक बन गये हैं। पहले विद्यार्थियों में गुरु के प्रति आदर भाव होता था। संस्कारमय परम्परागत मूल्यों के प्रभाव के कारण वातावरण शुद्ध था। शिक्षा राजनीति से दूर थी, परन्तु वर्तमान में इन सम्बंधों में तेजी से बदलाव आ रहा है। शिक्षा में राजनैतिक हस्तक्षेप, प्राध्यापकों का भौतिकवादी दृष्टिकोण, दोषपूर्ण सामाजिक वातावरण आदि इन सब घटकों ने शैक्षणिक वातावरण को प्रभावित किया है।

निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि वर्तमान में महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों की उपस्थिति घटती जा रही है, विद्यार्थी अध्यापन कार्यों में रूचि क्यों नहीं लेते यह सम्बंधित विषय के प्राध्यापकों एवं शासन को चिंतन करने एवं अपने कार्यों में रोचकता लाना अतिआवश्यक है ताकि उनकी उपस्थिति बढ़े एवं साथ ही 75 फीसदी से कम उपस्थिति होने पर छात्रवृत्ति पर रोक लगाई जाए, जो नियम है उसका कड़ाई से पालन हो। कई कॉलेजों/विश्वविद्यालयों में अधिकांश पद खाली पड़े हैं अतिथि विद्वानों से मानदेय पर अध्यापन होता है वे अस्थायी होते हैं, जिससे शिक्षण कार्य में गुणवत्ता नहीं आ पाती है अतः शासन को नियमित प्राध्यापकों की नियुक्ति उचित वेतनमान पर करनी चाहिए। परीक्षाओं को सीमित कर अध्यापन को अधिक समय दिया जाना चाहिए। अतः शासन का यह प्रयास हो कि बदलते हुए वैश्विक परिवेश में समाज का संतुलित विकास हो एवं उसके विभिन्न अवयवों के मध्य पारस्परिक सामंजस्य की स्थिति सुनिश्चित करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों के गुणात्मक विकास पर बल दिया जाना चाहिए।

संदर्भ ग्रंथ:—

मनोज कुमार सिंह — विजार्ड समसायिकी 2013 बी/19डॉ.मुखर्जी
नगर, दिल्ली

अनिल अग्रवाल — वार्षिक करंट अफेयर्स 7/5 मंथन प्रकाशन,
ताशकंद मार्ग, सिविल लाईन, इलाहाबाद

डॉ. उमेश कुमार सिंह — रचना (मई-अगस्त 2007) मध्यप्रदेश
हिंदी ग्रंथ अकादमी

मनोहर पाण्डे — अरिहंत सामान्य अध्ययन 4577/15 अग्रवाल
रोड़, दरियागंज, नई दिल्ली

Corresponding Author

Dr. Arjun Singh Bhaghel*

Assistant Principal (Commerce) Rani Durgawati Govt.
PG College, Mandla (MP)

E-Mail – arjunsinghb9@gmail.com